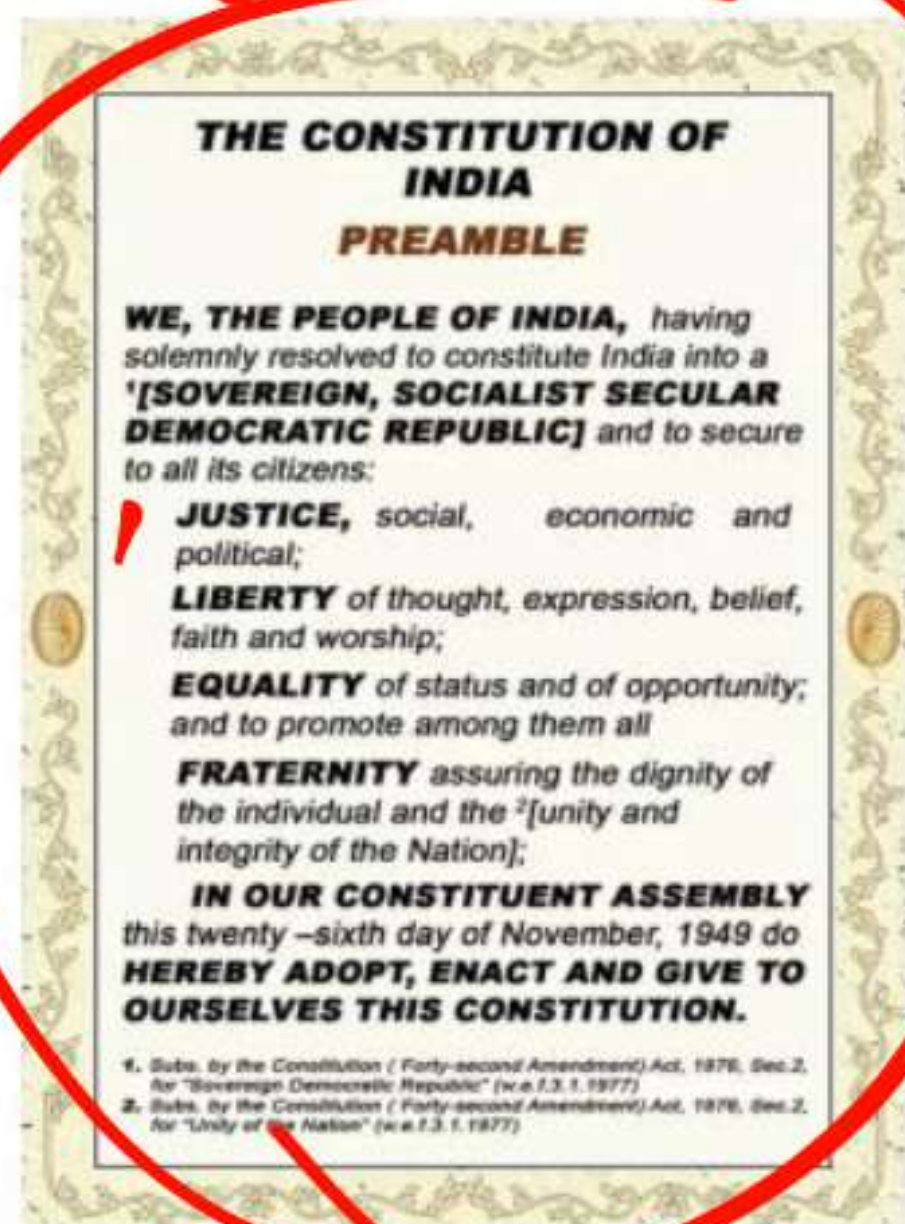




प्रस्तावना

उद्देशिका

Preamble of Indian Constitution



भारतीय संविधान
की प्रस्तावना

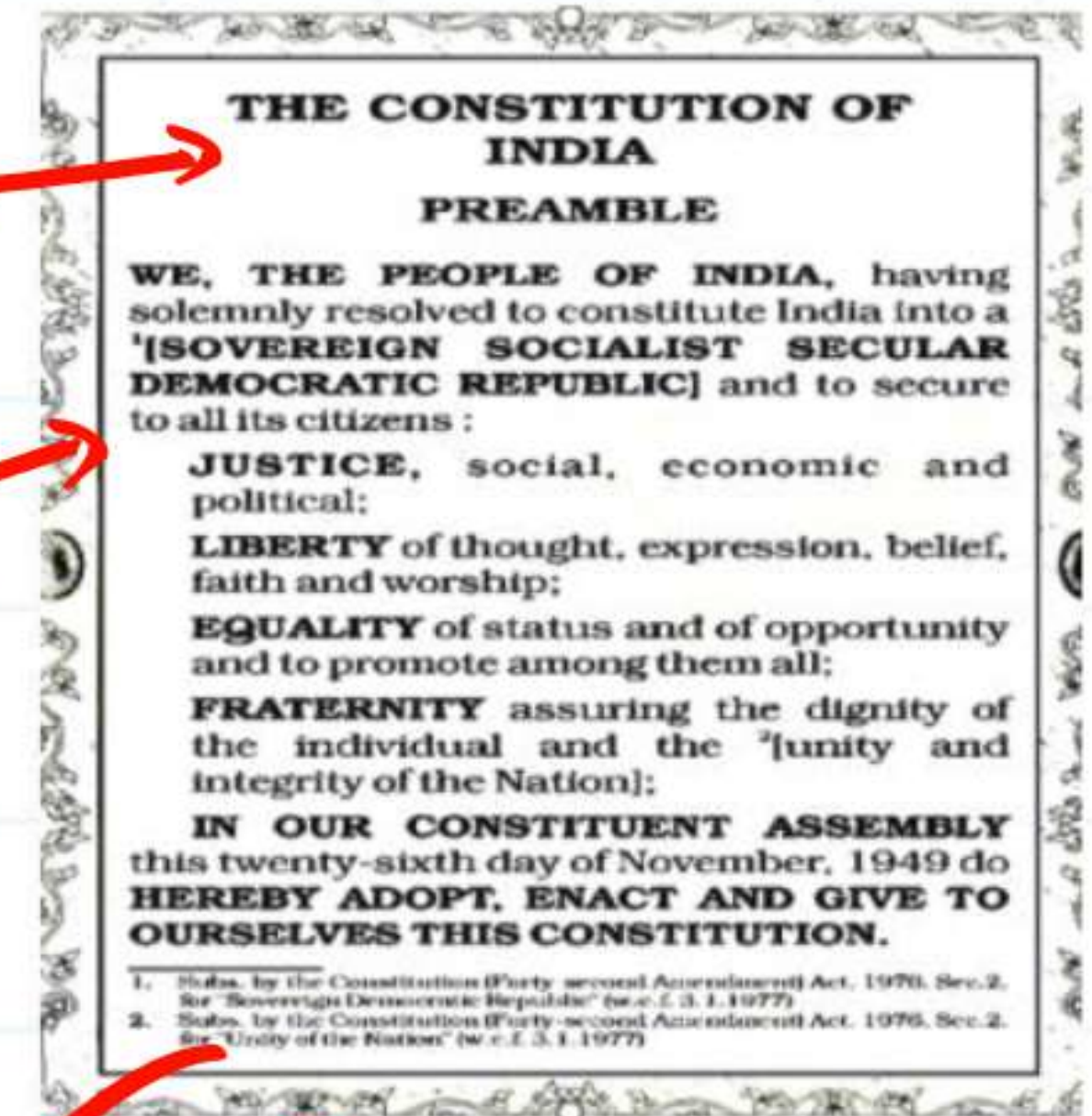


• The term 'Preamble' refers to the introduction or preface of the Indian constitution. / 'प्रस्तावना' शब्द का मतलब भारतीय संविधान की शुरुआत या परिचय है।

• It contains the summary or essence of the Constitution, along with the ideals and aspirations upon which the Indian state is founded. / इसमें संविधान का सारांश या मुख्य बातें होती हैं, साथ ही वे आदर्श और आकांक्षाएं भी होती हैं जिन पर भारतीय राज्य आधारित है।

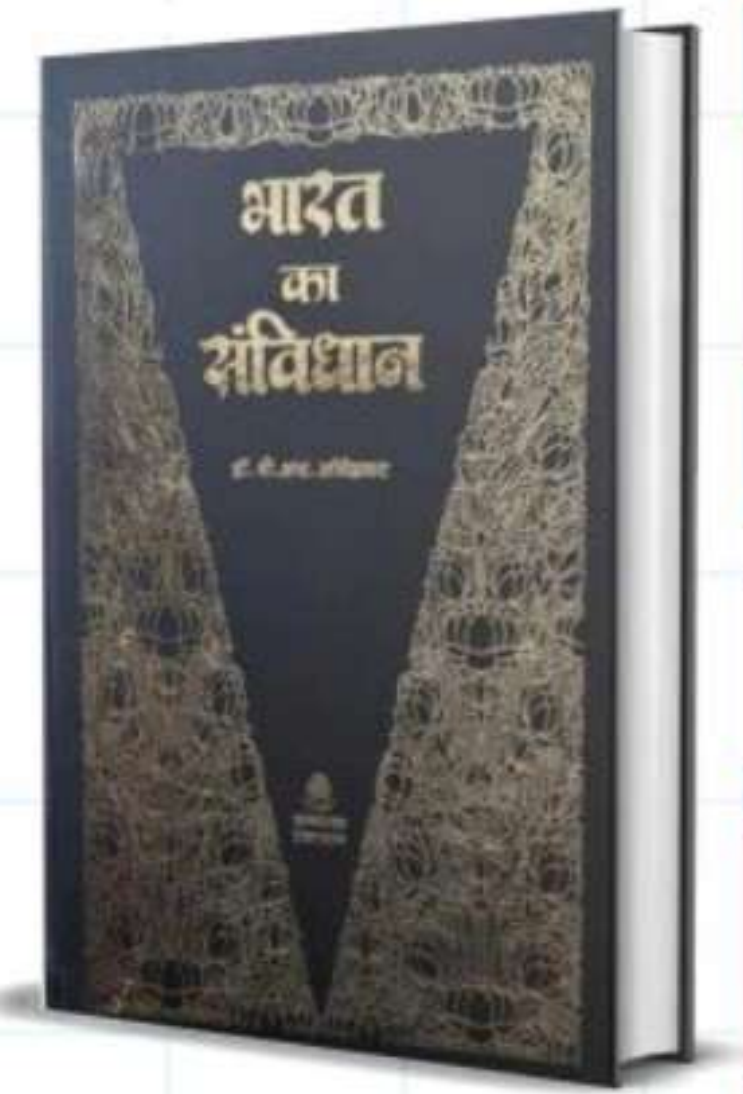
• An eminent jurist N.A. Palkhivala has called it the 'Identity Card of the Constitution'. / एक जाने-माने न्यायविद एन.ए. पालकीवाला ने इसे 'संविधान का पहचान पत्र' कहा है।

• Similarly, K.M. Munshi has described it as the 'Political Horoscope of the Constitution'. / इसी तरह, के.एम. मुंशी ने इसे 'संविधान की राजनीतिक कुंडली' बताया है।



Historical Background

- On December 13, 1946, Nehru moved the 'Objective Resolution' in the Constituent Assembly. / 13 दिसंबर, 1946 को नेहरू ने संविधान सभा में 'उद्देश्य प्रस्ताव' पेश किया।
- This resolution defined the basic goal or purpose of the Indian Constitution. / इस प्रस्ताव में भारतीय संविधान का मूल लक्ष्य या मकसद बताया गया था।
- It also acted as the guiding principle for the members of the constituent assembly in framing the constitution. / यह संविधान बनाने में संविधान सभा के सदस्यों के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत का भी काम करता था।
- The same resolution was adopted as the Preamble to the Indian Constitution on January 22, 1947. / इसी प्रस्ताव को 22 जनवरी, 1947 को भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में अपनाया गया था।



Text of the Preamble

- We, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens:/ हम, भारत के लोग, भारत को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने और इसके सभी नागरिकों को सुरक्षित करने का पक्का इरादा रखते हुए:
- JUSTICE, Social, Economic and Political;/ न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक;
- LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship; / विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता;
- EQUALITY of status and of opportunity and to promote among them all;/ स्थिति और अवसर की समानता और उन सभी के बीच बढ़ावा देना;
- FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation;/ भाईचारा जो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करता है;
- In Our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT, and GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION/ अपनी संविधान सभा में, आज 26 नवंबर 1949 को, हम इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और खुद को सौंपते हैं।





Components of the Preamble ✓

- **Source of authority for the Constitution** – The Preamble states that the Constitution derives its authority from the people of India./ संविधान का अधिकार स्रोत – प्रस्तावना में कहा गया है कि संविधान को भारत के लोगों से अधिकार मिलता है।
- **Nature of Indian State** – It declares India to be a Sovereign, Socialist, Secular Democratic, and Republican Polity./ भारतीय राज्य का स्वरूप – यह भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य घोषित करता है।
- **Objectives of the Constitution** – It specifies Justice, Liberty, Equality, and Fraternity as the objectives./ संविधान के उद्देश्य – यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को उद्देश्यों के रूप में बताता है। ✓
- **Date of adoption of the Constitution** – It stipulates November 26, 1949, as the date of its adoption./ संविधान को अपनाने की तारीख – यह 26 नवंबर, 1949 को इसे अपनाने की तारीख बताता है।



Key Words in The Preamble

- “We, the People of India”

→ संप्रभुता

- Sovereign

- Justice

→ न्याय

- Socialist

समाजवाद

- Liberty

स्वतंत्रता

- Secular

धर्मनिरपेक्ष

- Equality

समता

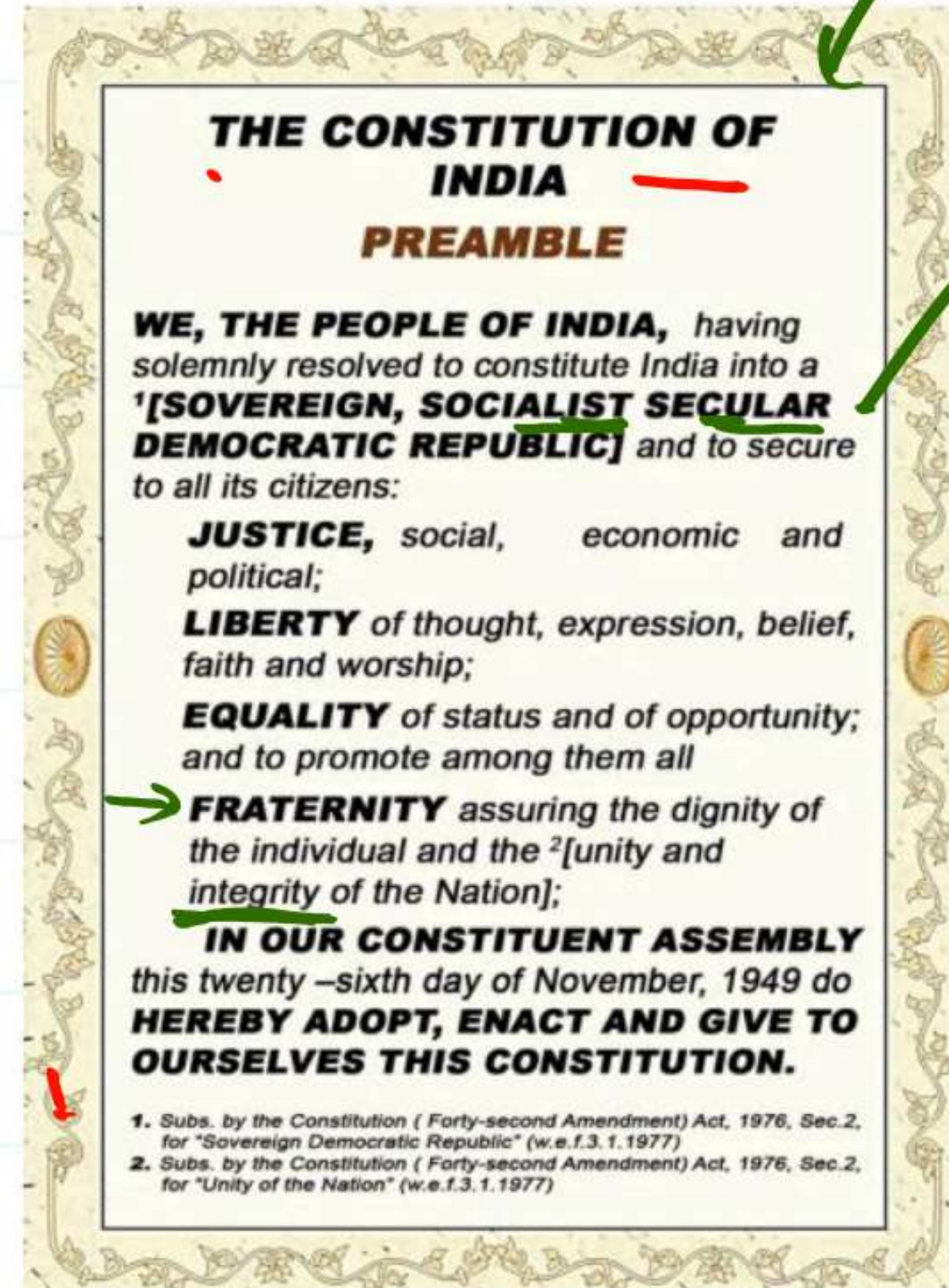
- Democratic

- Fraternity

- Republic

{ लोकतांत्रिक
वाणिज्य

→ भाईचारा
/ बंधुत्व



42nd
Amed.
1976

Major Issues and Judgments Related to the Preamble



Berubari Union Case, 1960

In this case, the Supreme Court made the following two observations regarding the Preamble of India/ इस केस में, सुप्रीम कोर्ट ने भारत के प्रस्तावना के बारे में ये दो बातें कहीं:

- **The Preamble is not a part of the Constitution./ प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है।**
- **Since the Preamble serves as the key to the minds of our Constitution makers, some assistance in interpreting any ambiguity in the Constitution can be taken from the Preamble. / क्योंकि प्रस्तावना हमारे संविधान बनाने वालों के विचारों की कुंजी है, इसलिए संविधान में किसी भी अस्पष्टता की व्याख्या करने में प्रस्तावना से कुछ मदद ली जा सकती है।**
- **Thus, the position of the Preamble after this judgment was that – The Preamble is not a part of the Constitution, though some assistance in the interpretation of the Constitution may be taken from it./ इस तरह, इस फैसले के बाद प्रस्तावना की स्थिति यह थी कि – प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, हालांकि संविधान की व्याख्या में इससे कुछ मदद ली जा सकती है।**



Kesavananda Bharati Case, 1973

- In this judgment, the Supreme Court reversed its stand on the Preamble and made the following observations/ इस फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना पर अपना रुख बदल दिया और ये बातें कहीं।
- The Preamble of Indian Constitution will now be considered a part of the Constitution./ अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना जाएगा।
- It will play an important role in the interpretation of statutes and other various provisions of the Constitution/ यह कानूनों और संविधान के दूसरे अलग-अलग प्रावधानों की व्याख्या में अहम भूमिका निभाएगी।



LIC of India Case, 1995 ✓

- The Supreme Court once again ruled that the Preamble is an integral part of the Constitution, but it cannot be directly enforced in a court of justice in India. (Reference: Article 14, Article 19 (1))
- सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर फैसला सुनाया कि प्रस्तावना संविधान का एक ज़रूरी हिस्सा है, लेकिन इसे भारत में सीधे कोर्ट में लागू नहीं किया जा सकता। (संदर्भ: अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 (1))

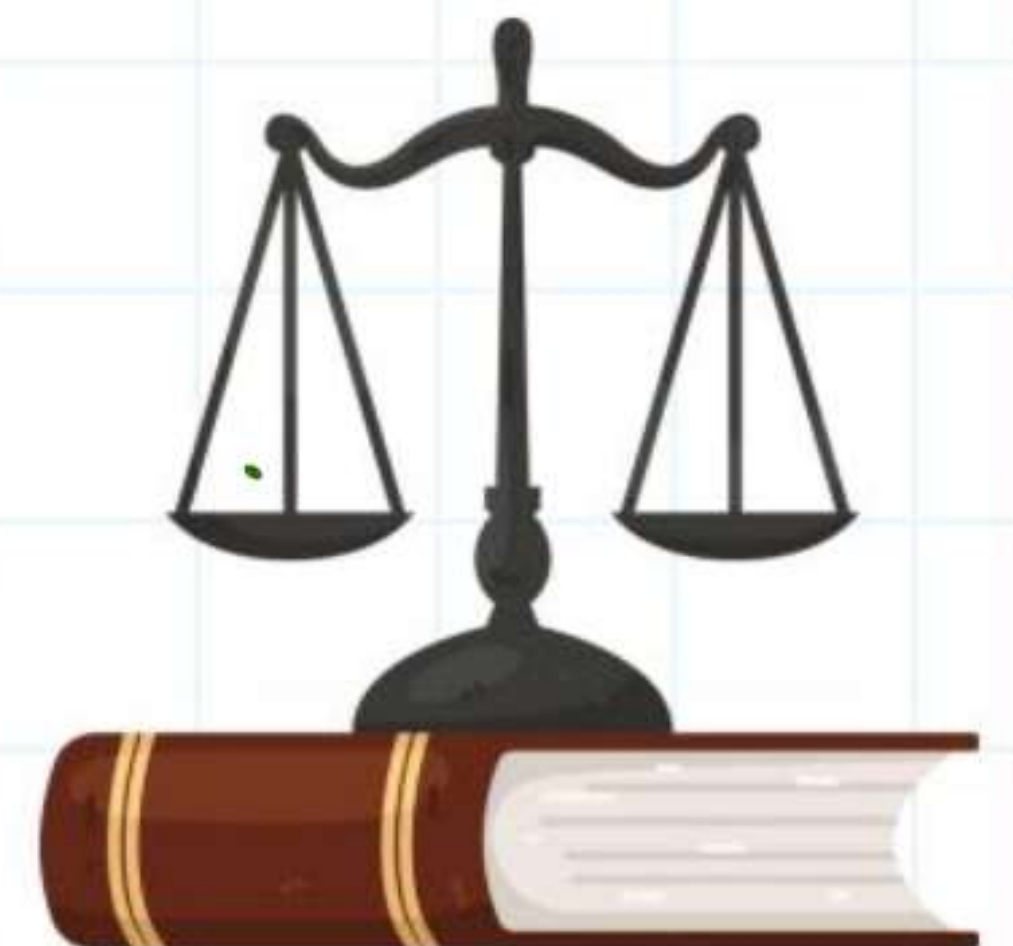
Equality before law



Amendment to the Preamble

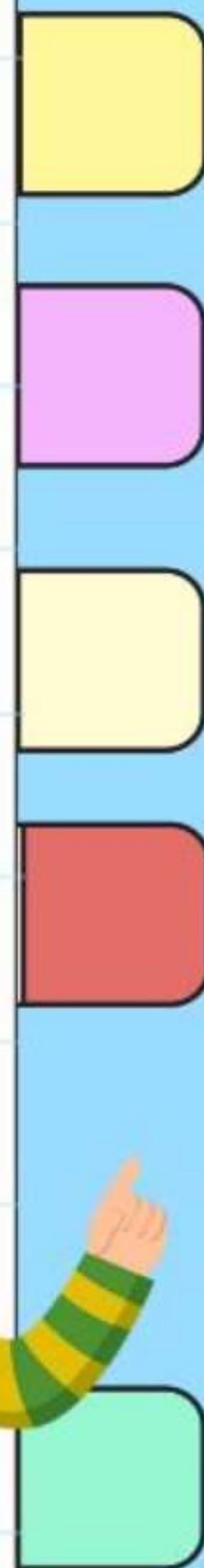
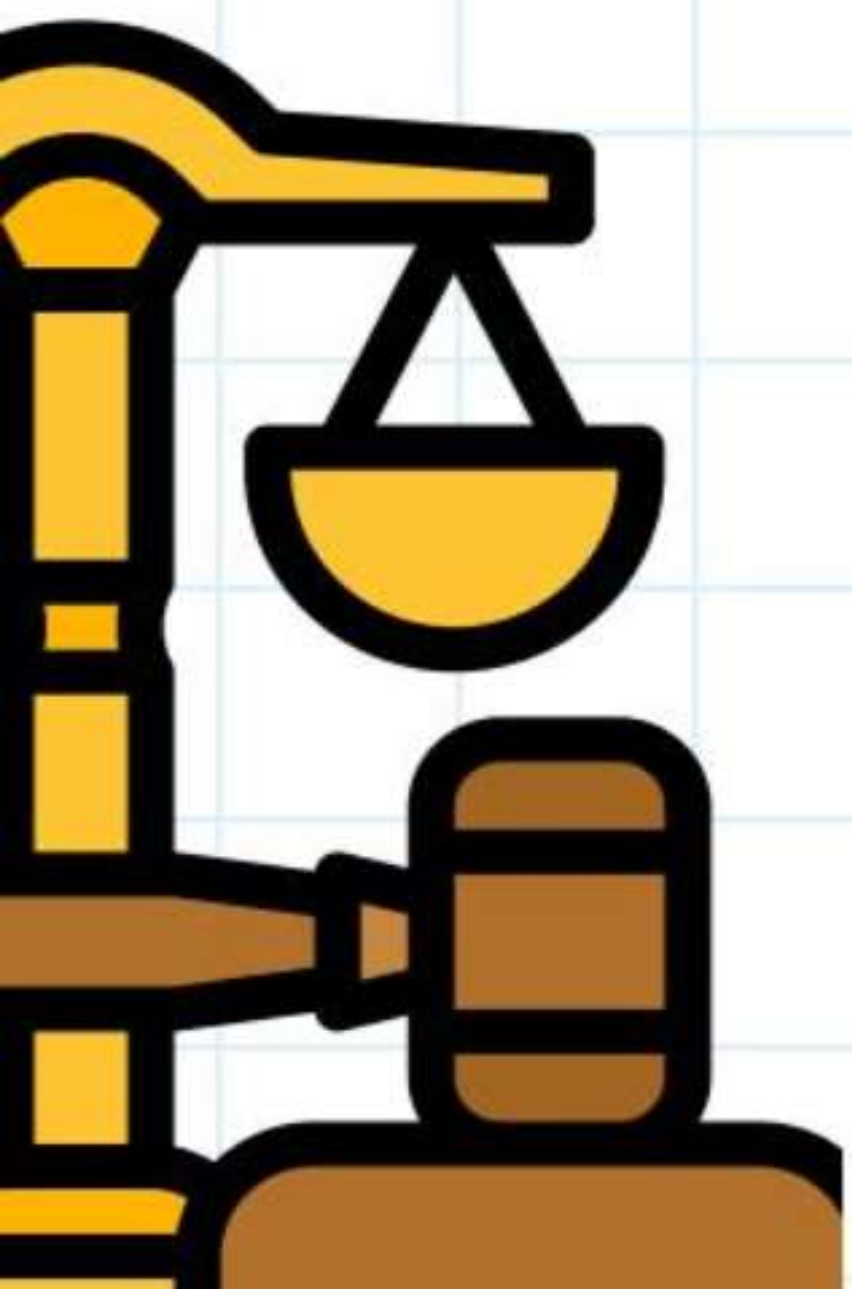
Mini
Const.

- The Preamble to the Constitution has been amended only once by the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976. / संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ एक बार 1976 के 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधन किया गया है।
- The amendment, which was made based on the recommendations of the Sardar Swaran Singh Committee, added three new words – Socialist, Secular, and Integrity – to the existing Preamble./ यह संशोधन, जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था, मौजूदा प्रस्तावना में तीन नए शब्द - समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता - जोड़े गए।
- 1 'Socialist' and 2 'Secular' were added between 'Sovereign' and 'Democratic'./ 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' को 'संप्रभु' और 'लोकतांत्रिक' के बीच जोड़ा गया था।
- 3 'Unity of the Nation' was changed to 'Unity and Integrity of the Nation'./ 'राष्ट्र की एकता' को बदलकर 'राष्ट्र की एकता और अखंडता' कर दिया गया।



THANK

YOU



Part 1



Union and Its Territories



संघ और उसके क्षेत्र



→ Part I : Art 1 - 4 (Union/संघ)

Part II : Art 5 - 11 (Citizenship/नागरिकता)

Part III : Art 12 - 35 (fundamental Rights
/ मौलिक अधिकार)

Introduction



- India is described as a 'Union of States' under Article 1 of the Constitution.
- संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत को 'राज्यों का संघ' कहा गया है।
- The term 'Union' emphasizes the indestructible nature of the Indian federation.
- 'संघ' शब्द भारतीय संघ की अविनाशी प्रकृति पर बल देता है।



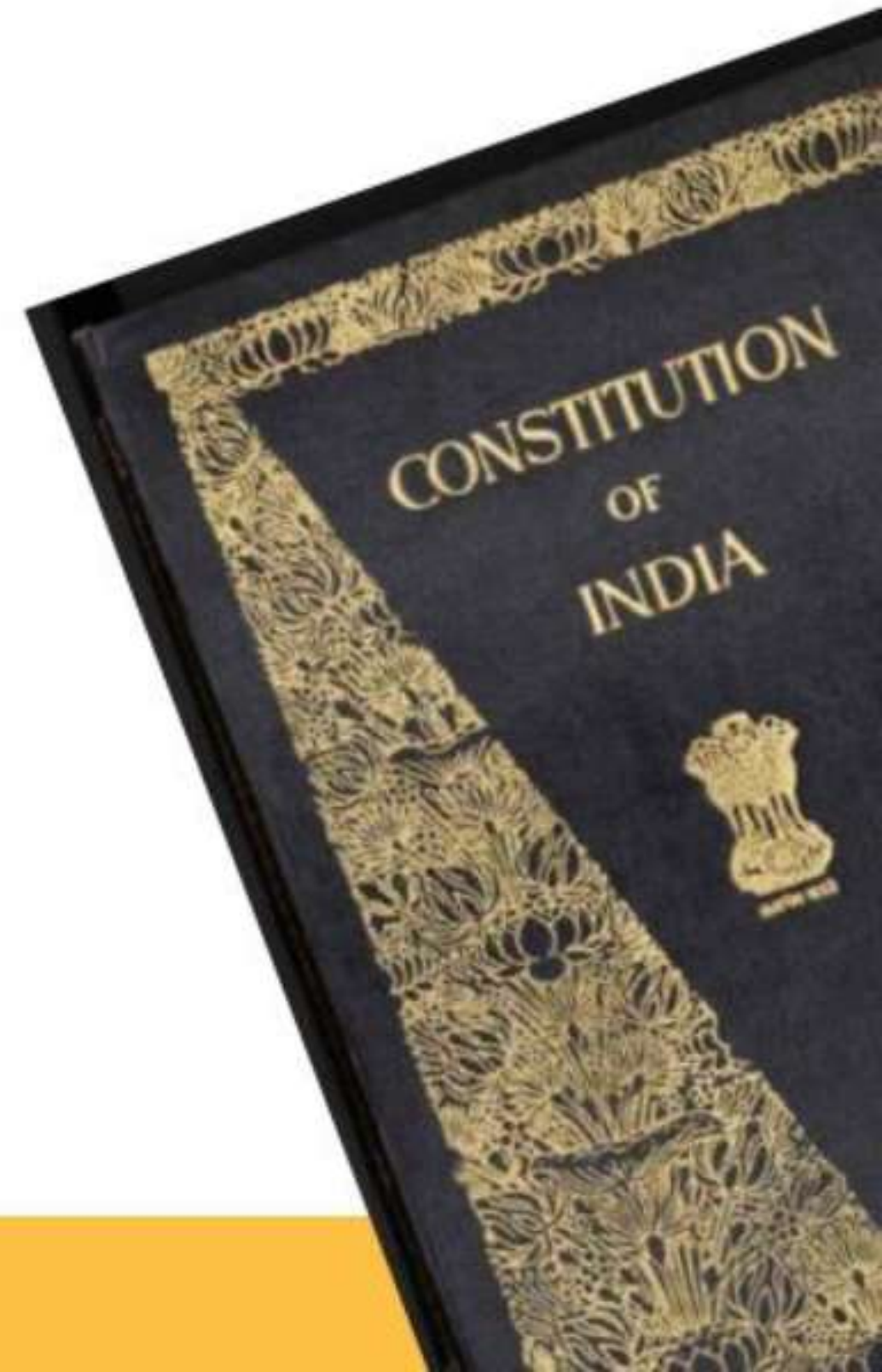
Article - 1

Name and Territory of India

भारत का नाम और

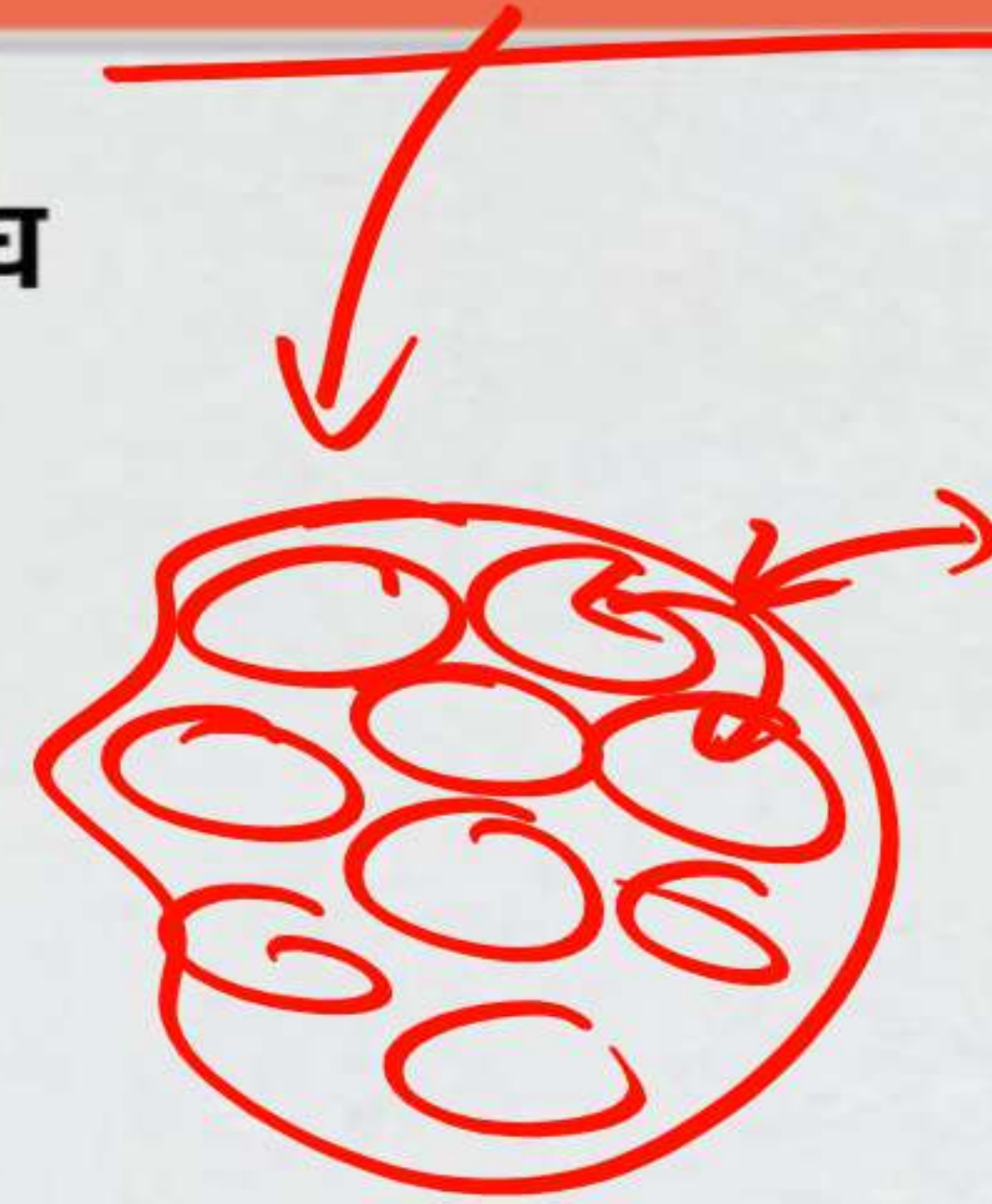
क्षेत्र

- India, that is Bharat, shall be a Union of States./
इंडिया, अर्थात् भारत, राज्यों का एक संघ होगा।
- Territory of India includes States, Union Territories, and any acquired territories./ भारत के क्षेत्र में राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और कोई भी अधिग्रहीत क्षेत्र शामिल हैं।



Why 'Union' and Not 'Federation'?

- The Indian Union is indestructible. / भारतीय संघ अविनाशी है।
- States have no right to secede from the Union./ राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है।
- The Union is created by the Constitution, not by an agreement among States./ संघ का निर्माण संविधान द्वारा होता है, राज्यों के बीच किसी समझौते से नहीं।



Article - 2 Admission or Establishment of New States

नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना

- Parliament may admit or establish new States.
- संसद नए राज्यों को शामिल या स्थापित कर सकती है।
- *Namgyal Dynasty*
- **Example:** Sikkim became part of India in 1975.
- उदाहरण: सिक्किम 1975 में भारत का हिस्सा बना।



Article -

Formation of New States and Alteration

3

नए राज्यों का गठन और

परिवर्तन

- Parliament can form new States, alter areas, boundaries, or names./ संसद नए राज्यों का गठन कर सकती है, क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है।
- Procedure / प्रक्रिया :
 1. Bill introduced in Parliament with President's recommendation./ राष्ट्रपति की अनुशंसा पर संसद में विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।
 2. President refers it to the concerned State Legislature for opinion./ राष्ट्रपति इसे संबंधित राज्य विधानमंडल की राय के लिए भेजते हैं।
 3. Parliament is not bound by the State's view./ संसद राज्य के विचार से बाध्य नहीं है।

2000



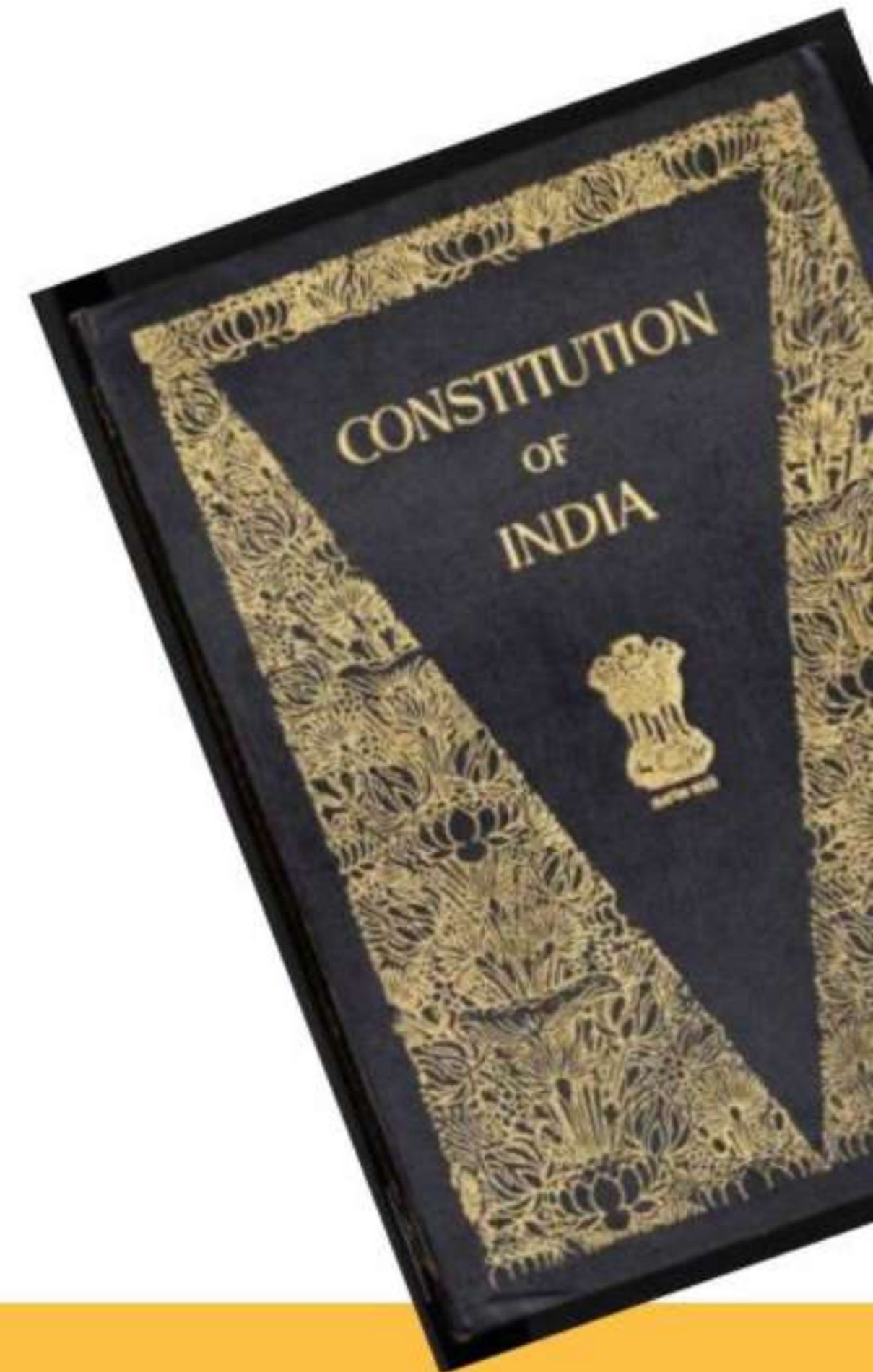
Article - 4

Laws Made Under Articles 2 and

3 अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून

➤ Such laws are treated as constitutional amendments./ ऐसे कानूनों को संवैधानिक संशोधन माना जाता है।

➤ But do not require a special majority or constitutional procedure under Article 368./ लेकिन अनुच्छेद 368 के तहत इन्हें विशेष बहुमत या संवैधानिक प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती।



Political Division of India

- India consists of 28 States and 8 Union Territories (as of 2025)./ भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं (2025 तक)।
- Governed under Article 1 of the Constitution./ संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत शासित।





TURKMENISTAN **UZBEKISTAN** **TAJIKISTAN** **AFGHANISTAN** **PAKISTAN** **CHINA** **NEPAL** **BHUTAN** **MYANMAR (BURMA)**

JAMMU & KASHMIR Srinagar Jammu
HIMACHAL PRADESH Dharamshala Shimla
PUNJAB Chandigarh
UTTERAKHAND Dehradun
HARYANA DELHI
NEW DELHI
RAJASTHAN Jaipur
UTTAR PRADESH Lucknow
BIHAR Patna
WEST BENGAL Kolkata
SIKKIM Gangtok
ARUNACHAL PRADESH Itanagar
ASSAM Dispur
MEGHALAYA Shillong
NAGALAND Kohima
MANIPUR Imphal
TRIPURA Agartala
MIZORAM Aizawl
GUJARAT Gandhinagar
DAMAN & DIU Daman
DADRA & NAGAR HAVELI Silvassa
MAHARASHTRA Mumbai
CHHATTISGARH Raipur
ODISHA Bhubaneswar
TELANGANA Hyderabad
ANDHRA PRADESH Amaravati
KARNATAKA Panaji
GOA
KERALA Thiruvananthapuram
TAMIL NADU Chennai (Madras) Puducherry
LAKSHADWEEP Kavaratti
ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS Port Blair

Bay of Bengal **Indian Ocean** **Andaman Sea** **SRI LANKA**

List of States and Their Capitals

- Andhra Pradesh: Amaravati
- Arunachal Pradesh: Itanagar
- Assam: Dispur
- Bihar: Patna
- Chhattisgarh: Raipur
- Goa: Panaji
- Gujarat: Gandhinagar
- Haryana: Chandigarh
- Himachal Pradesh: Shimla (Summer),
Dharamshala (Winter)
- Jharkhand: Ranchi
- Karnataka: Bengaluru
- Kerala: Thiruvananthapuram
- Madhya Pradesh: Bhopal
- Maharashtra: Mumbai (Summer),
Nagpur (Winter)
- Manipur: Imphal
- Meghalaya: Shillong
- Mizoram: Aizawl
- Nagaland: Kohima

List of States and Their Capitals

- **Odisha:** Bhubaneswar
- **Punjab:** Chandigarh
- **Rajasthan:** Jaipur
- **Sikkim:** Gangtok
- **Tamil Nadu:** Chennai
- **Telangana:** Hyderabad
- **Tripura:** Agartala
- **Uttar Pradesh:** Lucknow
- **Uttarakhand:** Dehradun (Winter),
Gairsain (Summer)
- **West Bengal:** Kolkata

Union Territories and Their Capitals

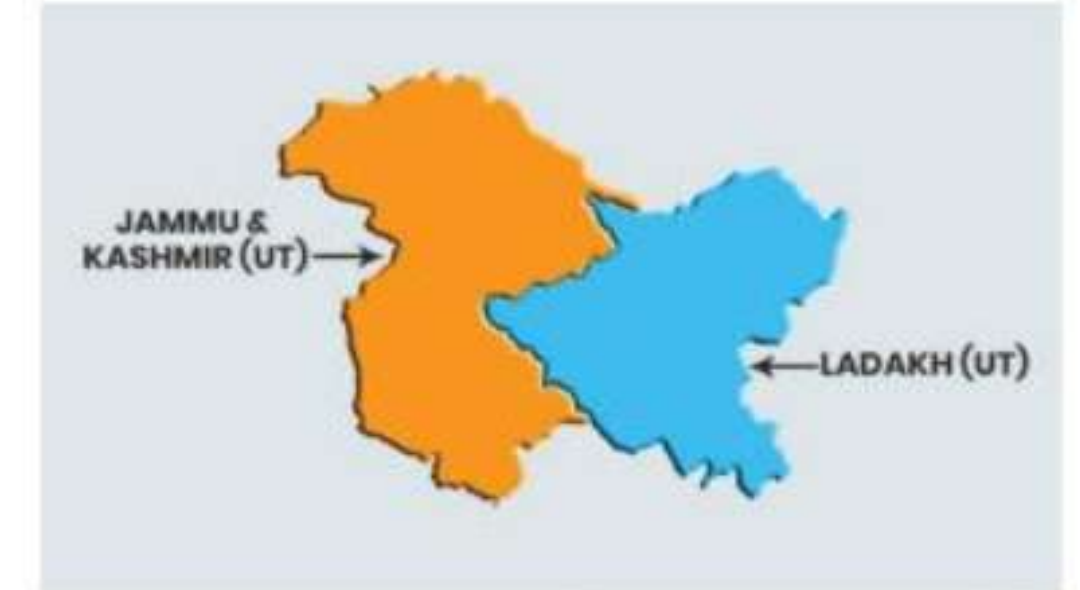
- Delhi – New Delhi
- Jammu & Kashmir – Srinagar (Summer), Jammu (Winter)
- Ladakh – Leh
- Chandigarh – Chandigarh
- Puducherry – Puducherry
- Andaman & Nicobar – Port Blair
- Lakshadweep – Kavaratti
- Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu – Daman



Recent Territorial Changes

हाल के क्षेत्रीय परिवर्तन

- **2019:** Jammu & Kashmir Reorganization Act – created J&K and Ladakh UTs. / जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम - जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया।
- **2020:** Merger of Daman & Diu with Dadra & Nagar Haveli into one UT. / दमन और दीव का दादरा और नगर हवेली के साथ विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया।



Special Status of Delhi (Article 239AA)

Part I

- Delhi is a National Capital Territory (NCT) with a Legislative Assembly. दिल्ली एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) है जिसमें एक विधानसभा है।
- Certain subjects like Police, Land, and Public Order remain with the Centre. पुलिस, भूमि और सार्वजनिक व्यवस्था जैसे कुछ विषय केंद्र के पास रहते हैं।

Importance of Territorial Division

Pre

- Ensures administrative efficiency./
प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करता है।
- Promotes unity in diversity./
विविधता में एकता को बढ़ावा देता है।
- Allows flexibility for new
territories./ नए क्षेत्रों के लिए लचीलापन
प्रदान करता है।



Health

State list

Quick recap

But!

संदर्भ

- Article 1 – Name and territory of India.

अनुच्छेद 1 - भारत का नाम और क्षेत्र।

- Article 2 – Admission/establishment of new States.

अनुच्छेद 2 - नए राज्यों का प्रवेश/स्थापना।

- Article 3 – Formation/alteration of States.

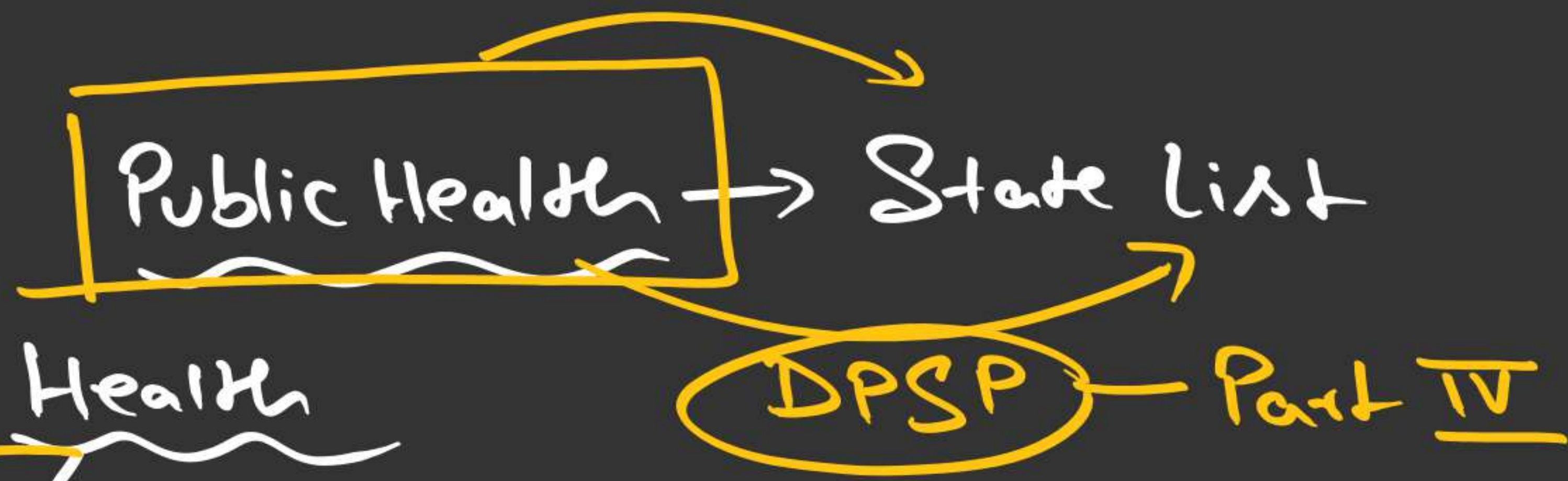
अनुच्छेद 3 - राज्यों का गठन/परिवर्तन।

Area
Name

- Article 4 – Nature of such laws.

अनुच्छेद 4 - ऐसे कानूनों की प्रकृति।





Health

State List $\Rightarrow$ Hospitals, Medicine, Drugs

X Union list $\Rightarrow$ International Disease prevention

X Concurrent list $\Rightarrow$ Cure, precaution & New Vaccination